

[2023] 10 एस. सी. आर 742:2023 आई. एन. एस. सी 607

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

ए.

द मद्रास एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड।

बी.

तमिल नाडु विद्युत बोर्ड और ए. एन. आर. (2009 की सिविल अपील संख्या 7224-7226)

बी.

06 जुलाई, 2023

[बी. आर. गवई, संजय करोल और अरविंद कुमार, जे. जे.]

अनुबंध-राज्य, अनुबंध के लिए एक पक्ष को अनुच्छेद 14 का पालन करना चाहिए-एक आवेदन पर विचार करने के लिए उचित अवधि-अपीलार्थी द्वारा 10000 किलोवोल्ट-एम्पीयर (केवीए) तक कम करने के लिए किया गया आवेदन-अपीलार्थी द्वारा बार-बार अनुवर्ती कार्रवाई के बावजूद इस तरह के अनुरोध को प्रभावी बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए-प्रत्यर्थीगणों की कार्रवाई, जब से उक्त आवेदन किया गया था, जब से संशोधित समझौता किया गया था, जब तक कि मनमाना और अनुचित था-आयोजित:हां-संविदात्मक क्षेत्र में होने के बावजूद राज्य की कार्रवाई को अनुच्छेद 14 का पालन करना चाहिए-अपीलकर्ता को अनुचित रूप से अप्रयुक्त बिजली के लिए लागत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, जिसे छह महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जाना चाहिए था (एक आवेदन पर विचार करने के लिए 'उचित अवधि' पर विचार करते हुए, ऐसा होना चाहिए), जिससे ऐसी कार्रवाई अनुचित और मनमाना हो जाती है-तथ्यों पर, प्रत्यर्थीओं के लिए यह तर्क देना खुला नहीं है कि याचिकाकर्ता 23000 केवीए का अधिकतम भार लेते हुए इस तरह से उत्पन्न बिलों के विरोध में जमा की गई राशि के रिफंड के लिए उत्तरदायी नहीं है-विशेष रूप से जब किसी भी समय, अपीलकर्ता ने न तो 10000 केवीए की अधिकतम मांग से अधिक बिजली की मांग की और न ही खपत की। धारा 3 (1) (ओ)।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

सिद्धांत/सिद्धांत-उचित समय का सिद्धांत-चर्चा-अनुबंध।

एच.

742 ए.

743

मद्रास एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड बनामतमिल नाडु विद्युत बोर्ड और ए. एन. आर.

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: **1.1** यह रिकॉर्ड की बात है कि जुलाई, **2004** में दोनों पक्षों के बीच **10000** केवीए की कम अधिकतम मांग के साथ एक नया समझौता किया गया था। निर्विवाद रूप से, **24** दिसंबर, **2001** को आवेदन किए जाने के ढाई साल से अधिक समय बाद इस तरह के नए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अपीलार्थी ने अधिकतम मांग में कमी के अनुसरण में अपना आवेदन दिया और अधिकारियों के साथ बार-बार संपर्क किया। बोर्ड की ओर से दो पत्रों को छोड़कर एक, उक्त आवेदन को स्वीकार करते हुए और यह बताते हुए कि इसे विचार के लिए अधिकारियों के समक्ष रखा गया है: और दो, इस तरह की कटौती की तारीख को अस्वीकार करना और कुछ शर्तों को सूचीबद्ध करना जिन पर इसे प्रदान किया जाएगा, बोर्ड की ओर से कोई अन्य संचार रिकॉर्ड नहीं बनाता है। [पारस **23,26**] [752-एच; 753-ए, ई]

बी.

सी.

1.2 इस विशेष आवेदन पर कार्रवाई करने के लिए इतने लंबे समय की आवश्यकता क्यों थी, इसका कोई कारण सामने नहीं आ रहा है। इस बीच अपीलार्थी को संपर्क विच्छेद के खतरे का सामना करना पड़ा है और इस तरह की निष्क्रियता के कारण उसे बिजली के लिए बड़ी राशि का भुगतान करना पड़ा है जिसका उसने उपयोग नहीं किया है। यह सच है कि समझौते में कहा गया है कि उपभोक्ता, (इसमें अपीलकर्ता) उपयोग की परवाह किए बिना ऐसी अधिकतम मांग राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य है और यह भी कि ऐसा समझौता पांच साल की अवधि के लिए प्रभावी होगा, लेकिन इस न्यायालय के सुविचारित विचार में, बोर्ड को इन खंडों की शरण लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जबकि दूसरी तरफ की कंपनी को इस तरह के निर्णय के अंतराल में भारी लागत का सामना करना पड़ता

है। **11 अगस्त 1994** के संचार को ध्यान में रखते हुए। [पैरा **27 और 28**] [753-एफ-एच]

डी.

ई.

एफ.

1.3 रिट कोर्ट ने कहा था कि अपीलार्थी द्वारा यहां उद्धृत अन्य मामलों में, तत्काल आवेदन के माध्यम से मांगी गई **13000** केवीए की कमी के विपरीत, कीवीए की एक छोटी राशि की कमी की मांग की गई थी। हालांकि यह सच हो सकता है, लेकिन यह किसी आवेदन को इतने लंबे समय तक लंबित रखने के कार्य का कारण नहीं देता है। [पैरा **29**] [754-ए-बी]

जी.

1.4 संविदात्मक क्षेत्र में होने के बावजूद राज्य की कार्रवाई को अनुच्छेद **14** का पालन करना चाहिए, और यह कि ए) एक महत्वपूर्ण पारित होने के बाद

एच.

744 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

ए.

जुलाई, **2004** में **10000** के. वी. ए. तक की कमी पर सहमति बनी और उस प्रभाव के लिए एक नया समझौता किया गया। बी) के. वी. ए. में कमी की राशि की परवाह किए बिना अन्य आवेदनों पर उचित समय के भीतर विचार किया गया था; ग) इस तरह के आवेदन को लंबित रखने का कोई कारण नहीं बताया गया है; घ) कि अपीलार्थी ने इस तरह की कमी को प्रभावी बनाने के लिए अधिकारियों के साथ विधिवत और बार-बार संपर्क किया; और ङ) अपीलार्थी को अनुचित रूप से अप्रयुक्त बिजली की लागत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, जिसे किसी भी मामले में छह महीने की अवधि से आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए था (किसी आवेदन पर विचार करने के लिए 'उचित अवधि' को ध्यान में रखते हुए), जिससे ऐसी कार्रवाई निर्विवाद रूप से अनुचित और मनमाना हो जाती है। तथ्यात्मक विवरण को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थागण के लिए यह तर्क देना खुला नहीं होगा कि याचिकाकर्ता इस प्रकार उत्पन्न बिलों के विरोध में जमा की गई राशि की वापसी के लिए उत्तरदायी नहीं है, जिसका अधिकतम भार **23000** केवीए है। विशेष रूप से, जब किसी भी समय अपीलार्थी ने न तो **10000** केवीए की अधिकतम मांग से अधिक बिजली की मांग की और न ही उसका उपभोग किया। अपीलार्थी की वित्तीय स्थिति को स्वीकार करते हुए, **1999** के समझौते में, प्रत्यर्थी को एक उचित प्रेषण और शर्तों के साथ अपीलार्थी के अनुरोध पर निर्णय लेना चाहिए था, जो ढाई साल के बजाय छह महीने की अवधि के भीतर

होना चाहिए था, जैसा कि अंततः किया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को दरकिनार कर दिया जाता है। [पारस **36-39**] [**756-F-G; 757-A-D**]

बी.

सी.

डी.

ई.

1.5 प्रत्यर्थी, तमिलनाडु विद्युत बोर्ड को निर्देश दिया जाता है कि वह **10,000** केवीए (**23000-10000 = 13000** केवीए) की अधिकतम स्वीकृत मांग के उसके अनुरोध से अधिक **13000** केवीए के लिए अपीलार्थी द्वारा भुगतान की गई राशि को वापस कर दे, जिसकी गणना और सत्यापन किया जा सकता है। ऐसी राशि की गणना आवेदन करने के छह महीने बाद यानी **24** दिसंबर, **2001** को जुलाई, **2004** में नए समझौते के निष्पादन की तारीख तक की जाएगी। यह स्पष्ट करते हुए कि यह अवधि **23** जून, **2002** से **1** जुलाई, **2004** (दोनों सहित) तक शुरू होनी है, उस पर लागू ब्याज **6** प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से सरल प्रकृति का होगा। सभी भुगतान आज से दो महीने के भीतर किए जाएंगे। [पैरा **40**] [**757-ई-एफ**] ए

एफ.

जी.

एच.

745

मद्रास एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड बनाम तमिल नाडु विद्युत बोर्ड और ए. एन. आर.

प्राकृतिक संसाधन आबंटन, पुनः, विशेष संदर्भ

2012 (2012) की संख्या 1 10 एस. सी. सी. 1: [2012] 9 एस. सी. आर. 311-
अनुसरण किया गया।

कुमारी श्रीलेखा विद्यार्थी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

और अन्य (1991) 1 एससीसी 212: [1990] 1 पूरका एससीआर

625; मानसराम बनाम एस. पी. पाठक और अन्य। (**1984**) 1 एससीसी

बी.

125 : [1984] 1 एस. सी. आर. 139; न्यायिक अधिकारी,

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड बनाम भावेश

पावरी (2019) 5 एस. सी. सी. 90-पर निर्भर था।

सांगयोंग एंग।& कंस्ट्रक्शन कं. लिमिटेड बनाम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(2019) 15 एससीसी 131:[2019] 7 एससीआर 522; गुजरात राज्य बनाम पटेल
राघव

सी.

नाथ (1969) 2 एस. सी. सी. 187:[1970] 1 एस. सी. आर. 335-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

डी.

[2019] 7 एससीआर 522

संदर्भित किया गया है

पैरा **21**

[2012] 9 एससीआर 311

पीछा किया।

पैरा **31**

[1990] 1 पूरक।एससीआर 625 पर भरोसा किया गया

पैरा **32**

(2019) 5 एस. सी. सी 90

उस पर भरोसा करें

पैरा **34**

ई.

[1984] 1 एससीआर 139

उस पर भरोसा करें

पैरा **35 [1970] 1 एस. सी. आर. 335** पैरा **35** को संदर्भित करता है।

सिविल अपील न्यायनिर्णय:2009 की सिविल अपील सं. 7224-7226।

एफ.

2003 के डब्ल्यू. ए. सं. 3806,3807 और 3808 में मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।

सी. ए. सुंदरम, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री रोहिणी मूसा, अभिषेक गुप्ता, जफर इनायत, सुश्री बीनू टम्टा, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

के. राधाकृष्णन, वरिष्ठ अधिवक्ता, डी. कुमानन, शेख एफ. कालिया, श्रीमती दीपा।एस., सुश्री दिव्या सिंह, विनोद कन्ना बी., अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

जी.

एच.

746

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

ए.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

संजय करोल, जे।

1. इस न्यायालय से जिन प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए कहा गया है, वे यह हैं कि क्या 10000 के. वी. ए. तक कम करने के लिए आवेदन किए जाने से लेकर संशोधित समझौता किए जाने तक काफी समय लेने में प्रत्यर्थीगणओं की कार्रवाई मनमाना और अनुचित थी? आकस्मिक रूप से, क्या अपीलार्थी 23000 के. वी. ए. और 10000 के. वी. ए. के लिए देय राशि के बीच के अंतर की राशि की वापसी का हकदार है, जिसका विरोध के तहत भुगतान किया गया है?

बी.

2. यह निर्णय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित 2003 के डब्ल्यू. ए. Nos.3806,3807 और 3808 में 15 दिसंबर, 2008 के निर्णय और आदेश से उत्पन्न अपीलों के एक समूह का निपटारा करेगा।¹

सी.

3. आक्षेपित निर्णय के माध्यम से, रिट अपीलीय क्षेत्राधिकार में बैठे न्यायालय ने 2002 के डब्ल्यू. पी. संख्या 19050-19052 में लर्नड सिंगल जज द्वारा पारित निर्णय और आदेश को बरकरार रखते हुए उक्त रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता (इसमें अपीलकर्ता, द मद्रास एल्यूमीनियम कंपनी)। लिमिटेड) अनुबंध के अनुसार शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य थे, भले ही 23000 केवीए 2 की खपत बिजली का अधिकतम अनुबंधित

भार हो। उच्च न्यायालय ने अपील में कहा कि इस तरह के विवाद पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए।

डी.

ई.

4. पिछली घटनाओं को तत्काल अपीलों को संदर्भ देने के लिए याद करने की आवश्यकता होती है। 4.1. अपीलार्थी एल्यूमीनियम के निर्माण के लिए 1965 में स्थापित एक कंपनी है, जो एक बिजली और बिजली गहन प्रक्रिया है। समय बीतने के साथ, इसे औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, भारत सरकार द्वारा बीमार औद्योगिक कंपनी अधिनियम, 1985 की धारा 3 (1) (ओ) के अनुसार एक 'बीमार औद्योगिक इकाई' घोषित किया गया था।

एफ.

4.2. 1994 में, वर्तमान प्रबंधन ने पुनरुद्धार की योजना के साथ बोर्ड से संपर्क किया, जिसके अनुसार सरकारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 165 के संदर्भ में कुछ अतिरिक्त रियायतों के साथ एक नई योजना जारी की गई थी।

जी.

1 इसके बाद, "विवादित निर्णय" 2 किलोवोल्ट-एम्पीयर।

एच.

3 बी. आई. एफ. आर. के रूप में संक्षिप्त। इसके बाद, "बोर्ड"

747

मद्रास एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड बनाम तमिल नाडु विद्युत बोर्ड और ए. एन. आर. [संजय करोल, जे।] ए.

ए.

दिनांक 21 दिसंबर 1994 और 37, दिनांक 10 फरवरी, 1995। वर्तमान प्रबंधन द्वारा मामलों को अपने हाथ में लेने के साथ, फरवरी, 1995 में उत्पादन शुरू हुआ। 4.3. मूल रूप से, समझौते के अनुसार अपीलार्थी के संयंत्र की बिजली की अधिकतम मांग 67000 केवीए थी। यह देखते हुए कि इस तरह की बिजली की खपत की लागत उत्पादन की लागत का 40 प्रतिशत से अधिक है, और यह कि कंपनी ने खुद एक कैप्टिव बिजली संयंत्र साबित किया था, एक अनुरोध किया गया था और इसके परिणामस्वरूप अनुबंधित अधिकतम मांग को 23000 केवीए तक कम करने के लिए सहमति व्यक्त की गई थी। यह समझौता 3 मई, 1999 4 के माध्यम से किया गया था।

बी.

सी.

4.4. इसके बाद अपीलार्थी ने 24 दिसंबर, 2001 को अनुबंधित अधिकतम मांग को 27 जनवरी, 2002 से घटाकर 10000 केवीए करने के लिए एक और अनुरोध किया, साथ ही इस तरह की कमी को लागू करने पर देय एकमुश्त शुल्क का भुगतान करने का प्रस्ताव भी दिया।

डी.

4.5. इस तरह का अनुरोध किए जाने और कुछ प्रारंभिक संचार के बावजूद, इस तरह के अनुरोध को प्रभावी बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। इसलिए, अपीलार्थी को 23000 केवीए की अनुबंधित मांग के अनुसार 320 रुपये प्रति केवीए की दर से भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा रहा था।

ई.

4.6. पिछले रियायती बिजली शुल्कों को वापस लेने और बार-बार उच्च मूल्य की मांगों के अलावा 25 मई, 2002 को पहले ही भुगतान किए गए सत्तर-आठ लाख (78,00,000) और बाद में भुगतान की गई राशि के साथ, विभिन्न मंचों के समक्ष याचिकाएं दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

एफ.

विवादित फैसला

5. विवादित निर्णय प्रत्यर्थीगणों के रुख को दर्ज करता है, 1999 के समझौते के विभिन्न खंडों और बिजली की आपूर्ति के नियमों और शर्तों पर भरोसा करते हुए उनके रुख को पूरी तरह से अनुमत होने के रूप में उचित ठहराता है। खंडों की सामग्री का उल्लेख करते हुए, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि बोर्ड द्वारा इसके संबंध में मंजूरी के अभाव में अपीलार्थी के लिए अनुबंधित मांग की तुलना में कम शुल्क का भुगतान करने का अधिकार नहीं है।

जी.

4 इसके बाद, "1999 समझौता"

एच.

748

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

5.1 यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि केवल इसलिए कि बोर्ड ने अपीलार्थीगण के आवेदन पर विचार करने में समय लिया, यह उन्हें स्वचालित रूप से कम राशि का भुगतान शुरू करने में सक्षम नहीं करेगा।

5.2 अपीलार्थीगण द्वारा उद्धृत अन्य उदाहरणों के संबंध में जहां समान रूप से रखे गए व्यक्तियों द्वारा इसी तरह के आवेदनों पर विचार किया गया था और बोर्ड द्वारा शीघ्रता से निर्णय लिया गया था, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि ऐसी याचिका पहली बार अपीलीय स्तर पर उठाई गई थी। यह भी देखा गया कि जिस तरीके से अपीलार्थी के आवेदन पर विचार किया गया वह मनमाना या अनुचित नहीं था और इस तरह के समझौते की व्याख्या रिट अधिकार क्षेत्र में नहीं की जा सकती थी। 6. हमने विद्वान वरिष्ठ वकील को सुना है; अपीलार्थी की ओर से श्री सी. ए. सुंदरम और प्रत्यर्थीगणों की ओर से श्री के. राधाकृष्णन। 7. 1999 के समझौते 4 में बिजली के आवंटन और आपूर्ति की आवश्यकता के बदले हुए परिदृश्य को स्वीकार करते हुए, विशेष रूप से, केंद्र सरकार द्वारा औद्योगिक इकाइयों को कैप्टिव बिजली संयंत्रों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई नीति को देखते हुए, कुल ऊर्जा कोटे को घटाकर अधिकतम 23000 केवीए करने के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तें शामिल थीं:

बी.

सी.

डी.

“लोड

अब इसे क्रमिक रूप से घोषित और अधिकतम रूप से सहमत किया गया है:

ई.

मांगें

इसके बाद के प्रावधानों के अधीन

निहित, बोर्ड की आपूर्ति और उपभोक्ता बोर्ड से 23000 केवीए से अधिक की अधिकतम मांग के लिए विद्युत ऊर्जा लेगा, जो पी. एन. पैटी गांव, मेट्टूर में अपने कारखाने के परिसर में उपर्युक्त उद्देश्य के लिए इसके विशेष उपयोग के लिए अनुबंधित भार में होगी। सलेम डी. उनके स्मेल्टर प्लांट और एक्सट्रैक्शन प्लांट एचटी एससी No.20 (अवैध) के लिए अनुबंधित भार 23000 केवीए होगा। उपभोक्ता अनुबंधित भार के रूप में अधिकतम मांग में कोई बदलाव नहीं करेगा।”

एफ.

जी.

*** ए.

एच.

749

मद्रास एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड बनामतमिल नाडु विद्युत बोर्ड और ए. एन. आर. [संजय करोल, जे।] ए.

6 का दायित्व। जिस तारीख से यह समझौता उपभोक्ता के लिए लागू होगा, वह सभी शुल्कों का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा और बोर्ड को मांग शुल्क, ऊर्जा शुल्क, बोर्ड द्वारा अधिकतम भुगतान करेगा।

अधिभार, मीटर किराया और अन्य शुल्क, यदि कोई हो, लागू शुल्क और बोर्ड द्वारा समय-समय पर अधिसूचित बिजली की आपूर्ति के नियमों और शर्तों के अनुसार, उपयुक्त उपभोक्ता वर्ग के लिए, जिससे वह संबंधित है।

बी.

बोर्ड का अधिकार 7. उपभोक्ता इस बात से सहमत है कि बोर्ड टू वेरी टर्म्स को समय-समय पर समझौते के समय, शुल्क, सामान्य और विविध शुल्क और इस समझौते के तहत बिजली की आपूर्ति के नियमों और शर्तों को विशेष या सामान्य कार्यवाही द्वारा बदलने का अधिकार होगा। उपभोक्ता, विशेष रूप से, इस बात से सहमत है कि बोर्ड को आवश्यकताओं के अनुसार बिजली की आपूर्ति के लिए देय दरों आदि को बढ़ाने का अधिकार होगा। बोर्ड के लिए किसी भी समय पूरी तरह से या आंशिक रूप से पव कटौती को प्रतिबंधित करने या लागू करने के लिए भी खुला है जैसा कि वह उचित समझता है।

सी.

डी.

ई.

पीरियाड ऑफ

11. यह समझौता लागू रहेगा।

समझौता

तारीख से पाँच साल की अवधि के लिए

इसका प्रारंभ खंड 2 में परिभाषित किया गया है और यह तब तक लागू रहेगा जब तक कि इसे किसी भी पक्ष द्वारा समाप्त नहीं कर दिया जाता है जैसा कि आपूर्ति की शर्तों में प्रदान किया गया है।”

एफ.

8. इसके अनुसरण में, अपीलार्थी ने 24 दिसंबर 2001 को एक संचार द्वारा प्रत्यर्थीगणों से बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता को कम करने के लिए बिजली की आपूर्ति की अधिकतम मांग को 10000 केवीए तक कम करने का अनुरोध भेजा। इसके बाद 27 जनवरी, 2002 के एक अनुस्मारक के माध्यम से प्रत्यर्थीगणों द्वारा 22 जनवरी, 2002 के अपने संचार के माध्यम से तथ्यों को स्वीकार किया गया, जिसमें अपीलार्थी को सक्षम प्राधिकारी के साथ विचार के लिए लंबित मामले के बारे में सूचित किया गया, और आवश्यक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की गई।

जी.

एच.

750

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

9. इस तरह के विचार को लंबित रखते हुए, प्रत्यर्थीगणों द्वारा 1999 के समझौते 4 के संदर्भ में निर्धारित मांग के लिए मासिक शुल्क के लिए बिल तैयार करने के साथ, अपीलार्थी के पास कोई विकल्प नहीं होने के कारण, उच्च न्यायालय सहित विभिन्न मंचों के समक्ष अपने अधिकारों का न्यायनिर्णयन करने के लिए मजबूर किया गया था।

10. इस तरह के निर्णय को लंबित रखते हुए, 24 दिसंबर 2001 के अपीलार्थी के अनुरोध के जवाब में, प्रत्यर्थीगणों ने निम्नलिखित रूप में सूचित किया:

बी.

“आई. बोर्ड के साथ मुकदमेबाजी, यदि कोई हो, का पता लगाने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा कटौती के प्रस्ताव को मंजूरी।

सी.

ii. कम मांग के लिए मीटरिंग व्यवस्था में संशोधन और कम मांग के लिए मौजूदा 230 केवीए माल्को एस. एस. को जारी रखने की तकनीकी आवश्यकता की जांच करने के बाद भी।

iii. मांग में कमी लाने से पहले आपूर्ति के नियमों और शर्तों के खंड 22.07 के अनुसार मांग के प्रत्येक के. वी. ए. के लिए प्रति के. वी. ए. अधिसूचित दर पर मांग शुल्क के दोगुने का एक बार भुगतान किया जाता है।

डी.

iv. कंपनी को कम मांग के लिए संशोधित समझौते को निष्पादित करना होगा और संशोधित परीक्षण रिपोर्ट लेनी होगी। 5. कम मांग के लिए सी. सी. बिल औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद ही उठाया जाएगा। तब तक सी. सी. बिल केवल मौजूदा स्वीकृत अधिकतम मांग के लिए लगाया जाएगा।”

ई.

11. यह रिकॉर्ड की बात है कि अंततः और लंबित कानूनों के बावजूद, पक्षों के बीच, अपने स्वयं के अधिकार के माध्यम से, प्रत्यर्हीगणों ने एक सचेत निर्णय लेते हुए 1999 के समझौते 4 को संशोधित किया, जिससे अधिकतम आवश्यक मांग 23000 केवीए से घटकर 10000 केवीए हो गई। यह जुलाई, 2004 की बात है।

एफ.

12. यह भी रिकॉर्ड की बात है कि 11 अगस्त, 1994 के संचार के माध्यम से, प्रत्यर्हीगणों ने, सैद्धांतिक रूप से, भार को कम करने के अनुरोध को आम तौर पर स्वीकार करने का निर्णय पहले ही ले लिया था, इसका प्रासंगिक उद्धरण निम्नानुसार है:

जी.

“उप:एच. टी. उपभोक्ताओं द्वारा अनुरोध की गई मांग में कमी-कुछ स्पष्टीकरण-जारी किए गए।

संदर्भ: सीई/डी/त्रिची एलआर। No.161666/Accts/A1/94 dt.21.7.94.

एच.

751

मद्रास एल्यूमीनियम कं. लिमिटेड v. तमिल नाडु विद्युत बोर्ड और ए. एन. आर. [संजय करोल, जे।] ए.

ए.

उपरोक्त के संदर्भ में, यह सूचित किया जाता है कि,

(1) आपूर्ति के नियमों और शर्तों के खंड 21.03 के अनुसार, "जब तक एक ही सेवा कनेक्शन में सभी बकाया का भुगतान नहीं किया जाता है, तब तक कोई अतिरिक्त भार/मांग स्वीकृत नहीं की जाएगी।" भार को कम करने की अनुमति देते समय भी इसे अपनाया जा सकता है।

बी.

(2) विवादित एच. टी. उपभोक्ताओं द्वारा अनुरोध किए गए भार को कम करने के लिए इसे संसाधित करने से पहले मुख्यालय कार्यालय को भेजा जा सकता है।

(3) पहले की कटौती की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर भार में कमी के अनुरोध की अनुमति दी जा सकती है।

सी.

13. अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि अनुबंधित मांग को घटाकर 10000 केवीए करने का अनुरोध 24 दिसंबर, 2001 को किया गया था और उसके बाद, इस संबंध में बार-बार पत्र और संचार किए गए हैं। 30 जनवरी, 2002 के पत्र के माध्यम से अपीलार्थीगण को सूचित किया गया था कि 27 जनवरी, 2002 से लागू की जा रही कटौती के संबंध में धारणा गलत थी और यह कुछ शर्तों के अधीन होगी।

डी.

14. इसके अलावा, 20 मई, 2002 के एक पत्र के माध्यम से, संबंधित प्राधिकारी के साथ एक बैठक का अनुरोध किया गया था। इसके बाद, आपूर्ति के विच्छेद की धमकी को स्वीकार करते हुए विरोध के तहत Rs.78,00,000/- का भुगतान किया गया। उक्त भुगतान को 27 मई, 2002 के पत्र के माध्यम से स्वीकार किया गया था और यह कहा गया था कि इसका 'विरोध' स्वरूप स्वीकार्य नहीं था। इस प्रकार यह भी सूचित किया गया कि विलंबित भुगतान अधिभार 1.5% प्रति माह भी लागू होगा। 15. 4 जून, 2002 के पत्र के संदर्भ में 28 नवंबर, 2002 के उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुरूप संशोधित बिलों का अनुरोध किया गया था, लेकिन रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि उनका जवाब दिया गया है।

ई.

एफ.

16. उच्च न्यायालय ने अपील में समझौते के विभिन्न खंडों पर विस्तार से विचार करते हुए कहा कि बोर्ड द्वारा इस तरह के अनुरोध को मंजूरी दिए जाने के अभाव में कम की गई राशि का भुगतान करने का ऐसा कोई अधिकार नहीं है।

जी.

17. यह प्रस्तुत किया जाता है कि बोर्ड द्वारा अनुरोध के अनुसार अनुबंध में बदलाव नहीं करने के एकतरफा आह्वान से अपीलार्थी को अनुचित लागत का सामना करना पड़ता है। इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि बोर्ड इस तरह की अनुमति देने के लिए बाध्य है एच.

752

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

कटौती तब तक की जाती है जब तक कि खंड 19.02 के अनुसार भुगतान किया जा रहा हो।

18. खंड 13.04 के अनुसार, जिसमें कहा गया है कि किसी भी उपभोक्ता द्वारा आपूर्ति के समझौते को एक महीने का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है, यह आग्रह किया जाता है कि 27 जनवरी, 2002 से 10000 के. वी. ए. तक कम करने की मांग करने वाले 24 दिसंबर, 2001 के अपीलार्थी के आवेदन को 13000 के. वी. ए. के संबंध में समझौते को समाप्त करने की सूचना माना जाना चाहिए, जिसे कम करने की मांग की गई है।

बी.

19. कुछ अन्य उदाहरणों के आधार पर जहां इसी तरह के आवेदनों पर कम समय के भीतर निर्णय लिया गया था, यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन पर विचार करने के लिए इतना बड़ा समय लेना मनमाना और अनुचित है।

सी.

20. प्रत्यर्थियों के तर्क का प्राथमिक जोर 1999 के समझौते में एक खंड है जिसे सुप्रा द्वारा पुनः प्रस्तुत किया गया है। प्रत्यर्थीगणों के अनुसार, इस खंड का प्रभाव यह है कि अपीलार्थी द्वारा की गई अधिकतम मांग में कमी के अनुरोध को तब तक कोई दर्जा प्राप्त नहीं होता है जब तक कि बोर्ड द्वारा इस तरह के अनुरोध पर कार्रवाई नहीं की जाती है और इस तरह की कमी की अनुमति देने वाला निर्णय नहीं लिया जाता है।

डी.

21. यह कानून का एक तय सिद्धांत है कि किसी अनुबंध में एकतरफा संशोधन नहीं किया जा सकता है। यह इस अदालत द्वारा सांगयोग एंग में देखा गया है।&

कंस्ट्रक्शन कं. लिमिटेड बनाम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 5

ई.

कि, "यह मामला होने के नाते, न्याय के एक मौलिक सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है, अर्थात्, किसी अनुबंध का एकतरफा जोड़ या परिवर्तन कभी भी किसी अनिच्छुक पक्ष पर थोपा नहीं जा सकता है, और न ही समझौते का कोई पक्ष दूसरे पक्ष के साथ किए गए सौदे को करने के लिए उत्तरदायी हो सकता है। स्पष्ट रूप से, इस तरह का आचरण इस देश में पालन किए जाने वाले न्याय के मौलिक सिद्धांतों के विपरीत होगा।

एफ.

22. दोनों पक्षों ने आग्रह किया है कि एकतरफा निर्णय लिया गया है। प्रत्यर्थागण का तर्क है कि अपीलार्थी ने अधिकतम मांग को 10000 केवीए तक कम करने के लिए अनुबंध में एकतरफा संशोधन किया है, जब उनके द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया जाता है। इसके विपरीत, अपीलार्थी का तर्क है कि उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर कार्रवाई नहीं करने के बोर्ड के एकतरफा निर्णय ने उनके लिए पूर्वाग्रह पैदा किया है। 23. यह रिकॉर्ड की बात है कि दोनों पक्षों के बीच 10000 केवीए की कम अधिकतम मांग के साथ एक नया समझौता किया गया था

जी.

5 (2019) 15 एससीसी 131 ए

एच.

753

मद्रास एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड बनाम तमिल नाडु विद्युत बोर्ड और ए. एन. आर. [संजय करोल, जे।] ए.

जुलाई, 2004 में। निर्विवाद रूप से, 24 दिसंबर, 2001 को आवेदन किए जाने के ढाई साल से अधिक समय बाद इस तरह के नए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

24. यह तर्क कि अन्य समान समझौतों को प्रत्यर्थागण द्वारा शीघ्रता से संसाधित किया गया है और यह केवल अपीलकर्ता है जिसका आवेदन अलग किया गया था, उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि जुलाई 2004 में पक्षों द्वारा किया गया नया समझौता भी विशेष रूप से इंगित करता है कि उपभोक्ता अधिकतम मांग या अनुबंधित मांग में किसी भी परिवर्तन को प्रभावित नहीं करेगा और पूरक समझौता वर्तमान समझौते की शर्तों के अधीन और उसके अतिरिक्त है।

बी.

सी.

25. ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय के इस अवलोकन का बल यह है कि 1999 के समझौते में यह भी कहा गया है, जैसा कि ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है, कि उपभोक्ता अधिकतम मांग में कोई परिवर्तन नहीं करेगा और उसी प्रतिबंध ने पूरक समझौते में भी अपना स्थान पाया है और इसलिए, बोर्ड की मंजूरी के बिना अधिकतम मांग में कोई परिवर्तन संभव नहीं है, जो कथित रूप से अपीलार्थी द्वारा यहां किया गया है।

डी.

26. अपीलार्थी ने अधिकतम मांग में कमी के अनुसरण में अपना आवेदन दिया और अधिकारियों के साथ बार-बार संपर्क किया। बोर्ड की ओर से दो पत्रों को छोड़कर एक, उक्त आवेदन को स्वीकार करते हुए और यह बताते हुए कि इसे विचार के लिए अधिकारियों के समक्ष रखा गया है: और दो, इस तरह की कटौती की तारीख को अस्वीकार करना और कुछ शर्तों को सूचीबद्ध करना जिन पर इसे प्रदान किया जाएगा, बोर्ड की ओर से कोई अन्य संचार रिकॉर्ड नहीं बनाता है।

ई.

27. इस विशेष आवेदन पर कार्रवाई करने के लिए इतने लंबे समय की आवश्यकता क्यों थी, इसका कोई कारण सामने नहीं आ रहा है। इस बीच अपीलार्थी को संपर्क विच्छेद के खतरे का सामना करना पड़ा है और इस तरह की निष्क्रियता के कारण उसे बिजली के लिए बड़ी राशि का भुगतान करना पड़ा है जिसका उसने उपयोग नहीं किया है।

एफ.

28. यह सच है कि समझौते में कहा गया है कि उपभोक्ता, (इसमें अपीलकर्ता) उपयोग की परवाह किए बिना ऐसी अधिकतम मांग राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य है और यह भी कि ऐसा समझौता पांच साल की अवधि के लिए प्रभावी होगा, लेकिन इस न्यायालय के सुविचारित विचार में, बोर्ड को इन खंडों की शरण लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जबकि दूसरी तरफ की कंपनी को इस तरह के निर्णय के अंतराल में भारी लागत का सामना करना पड़ता है। 11 अगस्त 1994 के संचार को ध्यान में रखते हुए।

जी.

एच.

754

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

29. रिट कोर्ट ने कहा था कि अपीलार्थी द्वारा यहां उद्धृत अन्य मामलों में, तत्काल आवेदन के माध्यम से मांगी गई 13000 केवीए की कमी के विपरीत, कीवीए की एक छोटी राशि की कमी की मांग की गई थी। हालांकि यह सच हो सकता है, लेकिन यह किसी आवेदन को इतने लंबे समय तक लंबित रखने के कार्य का कारण नहीं देता है।

30. उपरोक्त चर्चा इस प्रश्न को मार्ग प्रदान करती है कि क्या अनुचित अवधि के लिए लंबित आवेदन की ऐसी कार्रवाई को अपने आप में एक मनमाना और अनुचित कार्य के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

बी.

31. प्राकृतिक संसाधनों में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ

2012 6 का विशेष संदर्भ सं. **1** के माध्यम से आबंटन

राज्य को एक पक्ष के रूप में रखने वाले अनुबंधों के संबंध में जे. एस. खेहर, जे. (उस समय उनके अधिपति के रूप में) का अवलोकन किया गया, जैसा कि यहाँ नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:- “183. भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 की प्रयोज्यता के दायरे पर इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मानदंडों की संक्षिप्त व्याख्या की जा रही है, उन मामलों में जहां राज्य, उसके साधन और उनके पदाधिकारी संविदात्मक दायित्वों में लगे हुए हैं (जैसा कि वे ऊपर दिए गए पैरा 159 से 182 में निकाले गए निर्णयों से सामने आते हैं)। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 की कसौटी का सामना करने में सक्षम होने के लिए, यह पहले से ही मुख्य राय में व्यक्त किया जा चुका है कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और न्यायसंगत व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए इसे निष्पक्ष, उचित, गैर-भेदभावपूर्ण, पारदर्शी, गैर-मज़बूत, निष्पक्ष, पक्षपात या भाई-भतीजावाद के बिना होना चाहिए। निर्दिष्ट निर्णय उन सभी आवश्यकताओं का समर्थन करते हैं जहां राज्य, उसके साधन और उनके पदाधिकारी संविदात्मक लेनदेन में लगे हुए हैं। इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि संविदात्मक मामलों के संदर्भ में तैयार की गई सभी "सरकारी नीतियों" को उपरोक्त मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए। जबकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 एक उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है जिसमें प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ एक तर्कसंगत संबंध है, यह एक ही श्रेणी में आने वाले कई व्यक्तियों में से मनमाने ढंग से चुनने और चुनने की शक्ति की अनुमति नहीं देता है। इसलिए, मानदंड या प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए ताकि एक ही श्रेणी में आने वालों के बीच चयन कारण, निष्पक्ष खेल और गैर-मनमानेपन पर आधारित हो। भले ही विचार के क्षेत्र में आने वाले केवल दो दावेदार हों, एक स्पष्ट, पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ मानदंड या प्रक्रिया होनी चाहिए।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

6 (2012) 10 एससीसी 1 ए

755

मद्रास एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड बनामतमिल नाडु विद्युत बोर्ड और ए. एन. आर. [संजय करोल, जे।] ए.

यह इंगित करने के लिए कि दोनों में से किसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए।यही वह है जो पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।”

(जोर दिया गया) 32।कुमारी में इस न्यायालय के दो विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ श्रीलेखा विद्यार्थी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 7

बी.

यह देखा गया कि निजी पक्षों से संबंधित अनुबंधों और राज्य द्वारा एक पक्ष के रूप में किए गए अनुबंधों के बीच "एक स्पष्ट अंतर" मौजूद है।प्राथमिक अंतर यह है कि राज्य अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अपने कार्यों का निर्वहन करते हुए "सार्वजनिक भलाई और सार्वजनिक हित के लिए, जैसा कि उससे अपेक्षित है, निर्विवाद रूप से कार्य करता है।"उक्त कारक किसी भी लेन-देन में सार्वजनिक कानून की न्यूनतम आवश्यकताओं को लाने के लिए पर्याप्त है, जिसमें राज्य एक पक्ष है।यह तथ्य कि कोई विवाद संविदात्मक दायरे में आता है, राज्य को अनुच्छेद 14 की आवश्यकताओं का पालन करने के अपने दायित्व से मुक्त नहीं करता है।

सी.

33. इसके अलावा न्यायालय ने कहा था कि:

डी.

“24. राज्य को संविदात्मक क्षेत्र में डॉ. जेकिल और श्री हाइड के विभाजित व्यक्तित्व के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है ताकि संविधान के अनुच्छेद 14 के दायित्व को पूरा करने के लिए एक अनुबंध करते समय राज्य की सभी विशेषताओं को प्रभावित किया जा सके और उसके बाद उसे अनुबंध के निर्वाह के दौरान एक निजी निकाय के नए वस्त्र को सजाने के लिए राज्य के अपने लिबास को छोड़ने की अनुमति दी जा सके, जिससे वह केवल संविदात्मक दायित्वों और उससे निकलने वाले उपचारों के अधीन मनमाने ढंग से कार्य कर सके।यह

वास्तव में राज्य के रूप में इसके व्यक्तित्व की प्रकृति है जो महत्वपूर्ण है और इसे किसी भी क्षेत्र में अपने सभी कार्यों को चिह्नित करना चाहिए, न कि कार्य की प्रकृति, संविदात्मक या अन्यथा, जो इसके अधिनियम की वैधता की जांच करने के लिए अनुमत जांच की प्रकृति का निर्णायक है। अनुच्छेद 14 की आवश्यकता निष्पक्ष, न्यायसंगत और यथोचित रूप से कार्य करने का कर्तव्य होने के नाते, ऐसा कुछ भी नहीं है जो संविदात्मक मामलों में भी राज्य को हमेशा ऐसा कार्य करने की आवश्यकता की अवधारणा के खिलाफ है। राज्य के अधिनियमों के बीच एक बुनियादी अंतर है जो हमेशा सार्वजनिक हित में होने चाहिए और एक निजी व्यक्ति के कार्य जो समान गतिविधियों में लगे हुए हैं, मुख्य रूप से व्यक्तिगत लाभ के लिए हैं, जो सार्वजनिक हित को बढ़ावा दे सकते हैं या नहीं भी। इस तरह से देखने पर, जिसमें हमें कोई वैचारिक कठिनाई या कालातीतता नहीं मिलती है, हम अनुच्छेद की आवश्यकता का कोई कारण नहीं पाते हैं।

ई.

एफ.

जी.

7 (1991) 1 एससीसी 212

एच.

756

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

14 राज्य गतिविधि के संचालन को विनियमित करने के लिए संविदात्मक मामलों के क्षेत्र में भी इसका विस्तार नहीं होना चाहिए।”

(जोर दिया गया) 34। यह मामला इस बात पर निर्भर करता है कि अधिकारियों द्वारा अधिकतम मांग में कमी के लिए किसी भी आवेदन पर विचार करने के लिए 'उचित समय' क्या माना जाएगा। निर्णय लेने में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ

बी.

अधिकारी, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड बनाम भावेश पावरी **8**

यह देखा गया है: “... ऐसे निर्णय हैं जो मानते हैं कि जब सीमा की अवधि निर्धारित नहीं की जाती है, तो ऐसी शक्ति का प्रयोग उचित समय के भीतर किया जाना चाहिए। उचित समय क्या होगा, यह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, चूक/क्रानून की प्रकृति, पूर्वाग्रह के कारण, क्या तीसरे पक्ष के अधिकार बनाए गए थे, आदि पर निर्भर करेगा।”

सी.

35. मनसाराम बनाम एस. पी. पाठक और अन्य में। 9 इस न्यायालय ने

डी.

यह देखा गया कि जब किसी उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए कोई शक्ति मौजूद होती है तो उसका प्रयोग उचित समय के भीतर किया जाना चाहिए। यह देखा गया है कि यह सब बहुत अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है जिसके लिए पूर्ववर्ती को मजबूत करने की आवश्यकता है। फिर भी, न्यायालय गुजरात राज्य बनाम पटेल राघव नाथ 10 का उल्लेख करता है जिसमें आयुक्त के लिए बॉम्बे भूमि राजस्व संहिता की धारा 211 के तहत पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए एक वर्ष की अवधि बहुत लंबी पाई गई थी। जैसा कि यहाँ उल्लेख किया गया है, उचित समय के सिद्धांत का हाल ही में प्रतिभूतियों में दो-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पालन किया गया था और

ई.

भारतीय विनिमय बोर्ड बनाम सुनील कृष्ण खेतान और अन्य। **11.**

36. उपर्युक्त अच्छी तरह से साबित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए कि संविदात्मक क्षेत्र में होने के बावजूद राज्य की कार्रवाई को अनुच्छेद 14 का पालन करना चाहिए, और यह कि (क) काफी समय बीतने के बाद, जुलाई, 2004 में 10000 केवीए तक की कमी पर सहमति व्यक्त की गई थी और उस प्रभाव के लिए एक नया समझौता किया गया था। (बी) के. वी. ए. में कमी की राशि के बावजूद अन्य आवेदनों पर उचित समय के भीतर विचार किया गया था; (ग) इस तरह के आवेदन को लंबित रखने का कोई कारण नहीं बताया गया है; (घ) कि अपीलार्थी ने इस तरह की कमी को प्रभावी बनाने के लिए अधिकारियों के साथ विधिवत और बार-बार संपर्क किया; और (ङ)

एफ.

जी.

8 (2019) 5 एससीसी 90 9 (1984) 1 एससीसी 125 10 (1969) 2 एससीसी 187 11 (2023) 2 एससीसी 643 ए

एच.

757

मद्रास एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड बनाम तमिल नाडु विद्युत बोर्ड और ए. एन. आर. [संजय करोल, जे।]

अपीलार्थी को अनुचित रूप से अप्रयुक्त बिजली की लागत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, जिसे किसी भी मामले में छह महीने की अवधि से आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए था (किसी आवेदन पर विचार करने के लिए 'उचित अवधि' को ध्यान में रखते हुए), जिससे ऐसी कार्रवाई निर्विवाद रूप से अनुचित और मनमाना हो जाती है।

37. तथ्यात्मक विवरण को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थागण के लिए यह तर्क देना खुला नहीं होगा कि याचिकाकर्ता इस प्रकार उत्पन्न बिलों के विरोध में जमा की गई राशि की वापसी के लिए उत्तरदायी नहीं है, जिसका अधिकतम भार 23000 केवीए है। विशेष रूप से, जब किसी भी समय अपीलार्थी ने न तो 10000 केवीए की अधिकतम मांग से अधिक बिजली की मांग की और न ही उसका उपभोग किया।

बी.

सी.

38. अपीलार्थी की वित्तीय स्थिति को स्वीकार करते हुए, 1999 के समझौते 4 में, प्रत्यर्था को एक उचित प्रेषण और शर्तों के साथ अपीलार्थी के अनुरोध पर निर्णय लेना चाहिए था, जो ढाई साल की अवधि के बजाय छह महीने की अवधि के साथ होना चाहिए था, जैसा कि अंततः किया गया था।

डी.

39. उपरोक्त कारणों से, अपीलों की अनुमति दी जाती है। मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा 2003 के डब्ल्यू. ए. 3806-3807 और 3808 में पारित 15 दिसंबर 2008 के फैसले को खारिज कर दिया गया है।

40. हम प्रत्यर्था अर्थात् तमिलनाडु विद्युत बोर्ड को 10,000 केवीए ($23000 - 10000 = 13000$ केवीए) की अधिकतम स्वीकृत मांग के उसके अनुरोध से अधिक 13000 केवीए के लिए अपीलार्थी द्वारा भुगतान की गई राशि को वापस करने का निर्देश देते हैं, जिसकी गणना और सत्यापन किया जा सकता है। ऐसी राशि की गणना आवेदन करने के छह महीने बाद यानी 24 दिसंबर, 2001 को जुलाई, 2004 में नए समझौते के निष्पादन की तारीख तक की जाएगी। यह स्पष्ट करते हुए कि यह अवधि 23 जून, 2002 से 1 जुलाई, 2004 (दोनों सहित) तक शुरू होनी है, उस पर लागू ब्याज 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से सरल प्रकृति का होगा। सभी भुगतान आज से दो महीने के भीतर किए जाएंगे।

ई.

एफ.

41. तत्काल अपीलों में उठाए गए प्रश्नों का उत्तर ऊपर दिया गया है। 42. अपीलों की अनुमति दी जाती है और लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तो उनका निपटारा कर दिया जाता है।

जी.

दिव्या पांडे

अपीलों की अनुमति दी गई।

(सहायक: रूपांशी विरंग, एलसीआरए)

एच.